कार्यसूची सं.	1
बैठक का दिनांक	11.05.16
बैठक सं.	55

**दिनांक 10 फ़रवरी, 2016 को आयोजित 54 वीं एस एल बी सी बैठक
के कार्यवृत्तों की पुष्टि**

- दिनांक 10 फ़रवरी, 2016 को आयोजित 54वीं एस एल बी सी बैठक के कार्यवृत्त सभी संबंधित कार्यालयों को संप्रेषित किए गए हैं।
- सभा के द्वारा उपर्युक्त बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जा सकती है क्योंकि इस संबंध में संशोधन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

कार्यसूची सं.	2
बैठक का दिनांक	11.05.16
बैठक सं.	55

पूर्व में आयोजित एस एल बी सी बैठक में लिये गये निर्णय पर कृत रिपोर्ट

राज्य सरकार से संबंधित मामले

क्र.स.	से लंबित	विषय	झारखण्ड सरकार द्वारा पस्तुत बर्तमान स्थिति
3.1.1	22.03.2002	<p>भूमि अभिलेखों का अद्यतन(Updation) और टेनैन्सी एक्ट में आवश्यक संशोधन (एस पी टी एवं सी एन टी अधिनियम)</p> <p>राज्य सरकार द्वारा भूमि अभिलेखों का अद्यतन करना एवं टेनैन्सी एक्ट में आवश्यक परिवर्तन करना प्रस्तावित था जिससे कि,</p> <p>1. किसानों के द्वारा कृषि ऋण के आवेदन देते समय वे भूमि अभिलेख , जो की R.B.I के नियमों के तहत अनिवार्य है , बैंकों को उपलब्ध करा सके।</p> <p>2. राज्य के किसान एवं उद्यमी भूमि को कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में बैंक में रख कर कृषि, MSE, शिक्षा एवं आवास ऋण प्राप्त कर सके।</p>	<p>1. भूमि अभिलेखों के DIGITIZATION की कार्य दिसम्बर, 2016 तक पूरा कर लिया जाएगा.</p> <p>2. माननीय मंत्री श्री नीलकंठ सिंह मुंडा की अध्यक्षता में TAC की उप समिति की बैठक हो चुकी है। बैंक ऋण प्राप्त करने हेतु CNT/SPT एक्ट में आवश्यक अनुशंसा प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।</p> <p>3. अनुसूचित जनजाति के सलाहकार समिति की गठित उप समिति के माननीय सदस्य श्री जे.बी.तुबिद को बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों को प्रदत्त ऋण की सुचना की मांग की गई थी, जो उपलब्ध करा दी गई है।</p>
3.1.2.	22.03.2005	<p>पी डी आर अधिनियम में संशोधन - राज्य सरकार के द्वारा , एम पी और यू पी रिकवरी अधिनियम के तर्ज पर, जरूरी संशोधन करने का प्रस्ताव था, जिस के अनुसार बैंकों के द्वारा अपफ्रॉन्ट कोर्ट फीस के भुगतान न कर , रिकवरी की राशि से ही कोर्ट फी का भुगतान करना था एवं रिकवरी अधिकारी को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के संशोधित प्राबधान लागू करने का प्रस्ताव था।</p>	<p>राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा (झारखण्ड सरकार अधिसूचना संख्या 127 दिनांक 16.02.2013 के तहत 25% कोर्ट फीस का अपफ्रॉन्ट भुगतान, एवं शेष 75% का Case निष्पादन के बाद भुगतान करने के लिए अधिनियम की धारा 5 में बदलाव किया है, जो प्रस्ताव से भिन्न है। कुछ जिलों में उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार भी कार्रवाई नहीं हो रही थी।</p> <p>प्रधान सचिव , योजना एवं वित्त भाग ,झारखण्ड सरकार</p> <p>के द्वारा सभी जिला के उपायुक्तों को दिनांक: 9.02.16 को आयोजित बैठक में जिला स्तर पर अनुपालन हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं।</p>
3.1.4.	20.03.2009	<p>“ बिहार मनी लेन्डर एक्ट 1974 एवं नियम ” जो झारखण्ड में लागू है, में संशोधन</p> <p>46 वें बैठक में तय समय सीमा - 01 माह बिहार में लागू अधिनियम की प्रति झारखण्ड सरकार को समिति द्वारा प्रदान किया गया है।</p>	<p>RBI की तकनीकी गुप की अनुशंसा के आधार पर Advocate General से परामर्श लिया गया, जिसमे उन्होंने एक Expert Panel जिनकी इस विषय पर expertise प्राप्त हो, के गठन का परामर्श दिया है। EXPERT पैनल का गठन कर लिया गया है एवं इसकी पहली बैठक भी हो चुकी है। MONEY लेन्डर एक्ट में संशोधन हेतु आगे की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।</p>
3.1.5.	29.09.2010	<p>राज्य के सभी जिलों में, बैंकों में बकाया राशि की वसूली हेतु समर्पित वसूली अधिकारी (Dedicated Certificate</p>	<p>Dedicated Certificate Officer के रूप में अवकाश प्राप्त अधिकारियों की नियुक्ति हेतु “लोक मांग वसूली अधिनियम विधेयक” 2015 को विधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया है, जिसके उपरांत लोक वसूली अधिनियम 1914 में</p>

		Officer) को बहाल किया जाना 	संशोधन हेतु माननीय राष्ट्रपति की सहमति हेतु प्रस्ताव भेजा गया है पर अनुमोदन अब तक अप्राप्त है, पुनः स्मरण-पत्र भेजा गया है
3.1.6.	19.02.2002	राज्य में बैंक के खजाने की रक्षा एवं सुरक्षा व्यवस्था 46वें बैठक में तय की गई समय सीमा - 02 माह	SLBC, RBI एवं गृह विभाग के संबंधित विभाग के साथ समन्वय कर बैठक कर लिया गया है SLBC की उप-समिति की बैठक दिनांक 29.04.16 के निर्णय के आलोक में सभी जिला पुलिस अधीक्षक को झारखण्ड पुलिस के द्वारा CURRENCY CHEST की रक्षा एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु निर्देश दिया गया है
3.1.7.	01.12.2008	आरसेटी हेतु भूमि का आवंटन	<ul style="list-style-type: none"> • सभी जिलों में भूमि आवंटित कर दि गई है • रामगढ़ जिला में आवंटित भूमि आवंटित बैंक PNB के द्वारा अनुपयुक्त पाया गया, भूमि आवंटन का मामला AC के पास लम्बित है
3.1.8	9.05.13	नगरपालिका प्राधिकार क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में भवन निर्माण के अनुमोदन हेतु सक्षम अधिकारी की घोषणा हेतु अधिसूचना।	योजना एवं विकास विभाग के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है । समिति ने यह रिपोर्ट दिया है कि झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम पंचायती राज संस्थानों को बिल्डिंग प्लान के अनुमोदन की अनुमति नहीं देता है। ड्राफ्ट उपविधियां तैयार होने की प्रक्रिया में है।
3.1.9	27.05.14	रांची में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नियंत्रण कार्यालय,, एसएलबीसी, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के लिए उपयुक्त भूमि का आवंटन।	झारखंड सरकार के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक व नाबार्ड के कार्यालयों हेतु भूमि आवंटित किया गया झारखंड सरकार के द्वारा , उपायुक्त , रांची को,SLBC व BOI के संयुक्त प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करने का आदेश पारित किया गया पर इसमें आवंटन की सूचना अप्राप्त है
3.1.10	9.12.15	कई जिलों के उपायुक्त कार्यालयों से , बैंकों को SARFAESI एक्ट के तहत प्रशासनिक अनुमति प्राप्त होने में असामान्य विलम्ब हो रही है,झारखण्ड सरकार से आग्रह है की सभी जिला-प्रशासन को उपयुक्त दिशानिर्देश दिया जाय	योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा सभी जिलों के उपायुक्तों को आवश्यक दिशानिर्देश भेजा जा चुका है
3.1.11	3.12.15	झारखण्ड सरकार से आग्रह है की बैंकों से वित्त-पोषित एवं HYPOTHECTED सभी व्यावसायिक वाहनों के परमिट (PERMIT) नवीकरण के समय,संबंधित बैंकों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जमा करने को आवश्यक बनाया जाय,इससे बैंकों के ऋण खातों में रिकवरी में सहायता मिलेगी	परिवहन सचिव द्वारा जिला स्तर पर दिशानिर्देश जारी किया गया है एव यह विषय अनुपालित है

बैंक से संबंधित मामले **Issues Pertaining To Banks**

क्रं.स.	से लंबित	मामले	बर्तमान स्थिति
3.1.11	2013	आरसेटी भवन का निर्माण कार्य बीओआई, भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, पीएनबी, केनरा बैंक द्वारा शुरू नहीं किया गया है। संलग्नक सं. में लम्बित विवरणी संलग्न है।	<ul style="list-style-type: none"> • निम्नलिखित जिलों में RSETI भवन निर्माण का कार्य आवंटित बैंकों के द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया , <ul style="list-style-type: none"> a. SBI -1.गढ़वा (आवंटित भूमि पर जिला न्यायालय में केस दर्ज) 2.लातेहार- भवन के नक्सा पारित overhead H.T लाइन हटाने का काम शुरू) 3.पलामू-MORD के पास राशि हेतु आवेदन भेजा गया 3.साहिबगंज- कोई प्रगति नहीं b. Canara बैंक - सिल्ली-कोई प्रगति नहीं c. PNB - सराइकेला व रामगढ - कोई प्रगति नहीं
	मई 2015	RSETI से प्रशिक्षण प्राप्त CANDIDATES का बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्ध करवाना	<p>बैंकों के द्वारा विभिन्न RSETI यों में अब तक के प्रशिक्षित TRAINEES में से 4299 प्रशिक्षित लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है पर इन मुद्दे में काफी संख्या में आवेदन-पत्र बैंकों के द्वारा लौटाया गया या उनके पास लम्बित है, जबकि slbc द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका है कि CONTROLLING ऑफिस के अलावा शाखा स्तर से यह आवेदन नहीं लौटाया जा सकता है </p> <p>SLBC की उप समिति में इस विषय पर गहरी चिंता व्यक्त की गई एवं यह निर्णय लिया गया कि SPC, RSETI के द्वारा बैंक वार लम्बित आवेदन पत्र की सूची उपलब्ध करायी जाएगी ताकि बैंकों द्वारा शाखा स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके </p>

कार्यसूची सं.	3
बैठक दिनांक	11.05.2016
बैठक सं.	55

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के महत्वपूर्ण संकेतक (**KEY INDICATORS**)

		(Rs. in crore)			
Sl. No	KEY INDICATORS	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016	Bench Mark
1	Deposit	118646.05	139956.08	151224.54	
2	Credit	58202.91	65842.38	70728.48	
3	Credit as per place of utilization* & RIDF**	12552.84	20244.39	20923.84	
4	Total Credit	70755.75	86086.77	91652.32	
5	CD Ratio (%)	59.63	61.51	60.61	60
6	Priority Sector Advances (PSA)	41890.05	33736.07	38803.93	
7	Share of PSA to Total Advances(%)	71.97	51.23	54.86	40
8	Agricultural Advances	10186.33	11745.67	12858.56	
9	Share of Agricultural Advances to Total Advances (%)	17.50	17.83	18.18	18
10	i.Micro & Small Enterprises Advance	23391.42	13120.50	16458.93	
	iii.Share of Micro & Small Enterprises to Total Advances (%)	40.18%	19.92%	23.27%	
	ii.Share of Micro Enterprises in MSE	38.89%	51.22%	54.61%	
12	Advances to Weaker Sections	8304.03	11361.01	14689.94	
13	Share of Weaker Section Advances to Total Advances (%)	14.26%	17.25%	20.76%	10
14	DRI Advances	32.90	29.55	38.66	
15	Share of DRI Advances to Total Advances of last March (%)	0.06%	0.04%	0.05%	1
16	Advances to Women	10211.79	13200.38	16236.82	
17	Share of advances to women in Total advances (ANBC) (%)	17.54	20.05	22.95	5
18	Advances to Minorities (Amount)	3976.40	4869.83	5291.94	
19	Share of Advances to Minorities under PSC (%)	9.49%	14.43%	13.63%	15
20	N.P.A	3332.80	3680.70	4597.98	
	PERCENTAGE TO GROSS-CREDIT	5.72	5.59	6.50	
21	Branch Net-Work (in no.)-Rural	1341	1429	1469	
	Semi-Urban				
	Urban	695	720	745	
	Total	635	650	694	
		2671	2799	2908	
22	ATM installed in Jharkhand	2265	2608	2780	

*Annexure- V ,** Enclosure no -.5

As per Annexure - I,, Annexure-II ,Annexure-III, ,Annexure-IV

बैंकों के द्वारा दी जा रही आनुसांगिक सेवाएँ ,			
1	RSETI & RUDSETI	RSETI	24
		RUDSETI	1
2.	FINANCIAL LITERACY CAMPS	COMMERCIAL BANKS	1938
		R.R.B	256
3.	COVERAGE OF SSA WITH BANKING FACILITIES	SSA COVERED WITH BANKING FACILITIES	3277
		MICRO A.T.Ms	3209

पर्यवेक्षण

जमा वृद्धि

झारखंड राज्य में बैंकों की सकल जमा में पिछले वित्तीय वर्ष 15-16 में रूपये.11268.46 करोड़ की वर्ष-वार वृद्धि हुई है, 31 मार्च, 2016 के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि का दर 8.05 प्रतिशत दर्ज की गई है।

ऋण वृद्धि

राज्य में बैंकों के कुल क्रेडिट में रूपये 4886.10 करोड़ की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई , 31 मार्च, 2016 के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कुल ऋण वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि का दर 7.42 प्रतिशत दर्ज की गई है।

क्रेडिट - जमा अनुपात (C.D Ratio)

बैंकों का सीडी अनुपात 61.51 % , पिछले एक साल में घट कर, 60.61 % हुआ है।

(31 मार्च, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक) , इसका मूल कारण जमा वृद्धि का वार्षिक-दर, जो कि 8.05 % है का , ऋण-वृद्धि का वार्षिक दर से , जो कि 7.42 % है, ज्यादा होना है। परंतु पिछली तिमाही में C.D Ratio 59.45% से बढ़कर 60.61 % हो गया है

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम वर्ष में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 31 मार्च, 2016 को रू. 5067.86 करोड़ (15.02 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गयी है। वर्तमान में समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अग्रिम कुल अग्रिम का 54.86 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 40 प्रतिशत से काफी ज्यादा है।

कृषि अग्रिम Agriculture Credit

31 मार्च, 2016 को कृषि अग्रिम रू. 12858.56 करोड़ है जो कुल अग्रिम का 18.18 प्रतिशत है। पिछले एक साल में कृषि ऋण में कुल रू. 1112.89 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है यानि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 9.47 प्रतिशत की वृद्धि है।

कमजोर वर्ग Weaker Section

झारखण्ड राज्य में कमजोर वर्ग को रूपये 14689.94 करोड़ (20.76 प्रतिशत) का ऋण दिया गया है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 10 प्रतिशत से काफी बेहतर है।

महिलाओं को ऋण Advance to Women

31 मार्च, 2016 तक महिलाओं को रूपये 16236.82 करोड़ का ऋण दिया गया है जिसमें वर्ष -दर- वर्ष आधार पर रूपये 3036.44 करोड़ वृद्धि दर्ज की गई है, जो की लगभग 23 % वृद्धि है।

अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण Advance to Minority Community

अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण रूपये 4869.83 करोड़ से, पिछले एक साल में बढ़ कर रूपये 5291.94 करोड़ रूपये हो गया है। इसमें वर्ष -दर- वर्ष आधार पर 8.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का 13.63 % है, जो मानक 15 प्रतिशत से कम है।

31 मार्च, 2016 को राज्य का ऋण-जमा अनुपात

भारतीय रिजर्व बैंक के MASTER CIRCULAR. No – RPCD.CO.LBS.BC.No. 9/02.01.001/2014-15 , दिनांक 1.07.14 के अनुसार बैंकों का ऋण जमा अनुपात का मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर (एस एल बी सी) उपयोग और आर आई डी एफ के अनुसार किया जाना है।

तदनुसार, झारखण्ड राज्य का ऋण –जमा अनुपात निम्नवत है :-

(Rs in crore)

DETAILS		31 ST March, 2015	31 March , 2016	
Aggregate Deposits		139956.08	151224.54	
CORE ADVANCES	65842.38		70728.48	
As per place of Utilization	16966.98		17249.69	
RIDF	3277.41		3674.15	
NET ADVANCES	86086.77		91652.32	
ऋण-जमा अनुपात		61.51%	60.60%	

(परिशिष्ट-4, परिशिष्ट - 5)

नोट : कृपया ऋण – जमा अनुपात का विस्तृत विश्लेषण हेतु संलग्नक का संदर्भ लें जिसमें विभिन्न पैरामीटर ग्रामीण/अर्द्धशहरी/शहरी केन्द्र, बैंकवार और जिलावार समीक्षा आदि संबंधित पूर्ण विवरण संलग्न है।

कार्यसूची सं.	4
बैठक का दिनांक	11.05.16
बैठक संख्या	55

**4.1 वार्षिक ऋण योजना 2015-16 के तहत :
उपलब्धियों की समीक्षा : 31 मार्च, 2016 तक**

समग्र स्थिति

31 दिसम्बर, 2015_ की स्थिति

के अनुसार वार्षिक ऋण योजना 2015-16 के क्रियान्वयन में बैंकों का पिछले वर्ष की तुलना में
सेक्टर वार उपलब्धि:
... (रु करोड़ में)

SECTOR	ANNUAL TARGET (2014-15)	ACHIEVEMENT IN AFY 2014-15		ANNUAL TARGET (2015-16)	ACHIEVEMENT IN AFY 2015-16	
	AMT	AMT.	%	AMT.	AMT	%
1	2	3	4	5	6	7
Agriculture	6335.00	3040.94	48	7078.38	3690.64	52.13
MSE	5532.95	4564.19	82.49	6130.67	6460.62	105.38
OPS	2957.73	1817.89	61.35	3097.87	1768.68	57.09
Total Priority	14830.68	9423.02	63.53	16306.92	11919.94	73.10
Non Priority	9689.48	9289.68	95.87	10616.76	12138.77	114.33
Total	24520.16	18712.70	76.31	26923.68	24058.71	89.35

दिसम्बर तिमाही तक ACP 2014-15 & ACP 2015-16 में किया गया संवितरण का तुलनात्मक विवरण

Sector	Disbursements In ACP 2014-15	Disbursements In ACP 2015-16	Enhancement in Disbursements in AFY 2015-16 from AFY 2014-15	PERCENTAGE INCREASE
1	2	3	4	5
Agriculture	3040.94	3690.64	649.70	21.36
MSE	4564.19	6460.62	1896.43	41.55
OPS	1817.89	1768.68	(-)49.21	(-)2.70
Total Priority	9423.02	11919.94	2496.92	26.50
Non Priority	9289.68	12138.77	2849.09	30.67
Total	18712.70	24058.71	5346.01	28.57

टिप्पणियां :

- ✚ वार्षिक ऋण योजना 2015-16 में, वार्षिक ऋण योजना 2014-15 की तुलना में, सभी ऋण के संवितरण में काफी वृद्धि हुई है। यह उत्साहवर्धक बिषय है।
- ✚ कृषि क्षेत्र में, वार्षिक ऋण योजना 2015-16 में रु 3690.64 करोड़ रुपये का शुद्ध संवितरण, जो कि पिछले वित्त-वर्ष से रु. 649.70 करोड़ अधिक है, अत्यंत उत्साहजनक है एवं फलस्वरूप कृषि ऋण की

संवितरण में SLBC एवं सभी सदस्य बैंकों के बढ़ती हुई रूचि के कारण कुल ऋण में कृषि ऋण का प्रतिशत बढ़कर 18.18% हो गया , जो कि राष्ट्रीय बेंच-मार्क 18% से ज्यादा है |

- ✚ झारखंड राज्य के बैंकों को राज्य के बाहर मंजूर किये गए क्रेडिट सीमा जिन्हें झारखंड के अंदर उपयोग किया जा रहा हो, उन संवितरणों को राज्य में स्थित बैंकों के शाखाओं के द्वारा किये गये संवितरण के साथ समाहित करने के लिए अपने कॉर्पोरेट कार्यालय से संपर्क करना चाहिए |
- ✚ साथ ही, C.D Ratio निर्धारण के समय इस बात पर भी यथोचित सावधानी बरती जानी चाहिए कि “झारखण्ड के बाहर स्वीकृत परंतु झारखण्ड राज्य के अंदर उपयोग में लाये जाने वाली ऋण राशि” को एक ही बार कुल ऋण OUTSTANDING के साथ जोड़ा जाय एवं C.D Ratio पर इसका दोहरा प्रभाव न पड़े |

ANNUAL CREDIT PLAN 2016-17

- राज्य के सभी अग्रणी जिला प्रबंधक कार्यालयों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये नाबार्ड द्वारा प्रवर्तित "Potential Linked Plan" के व्यापक रूपरेखा के आधार पर "वार्षिक ऋण योजना" तैयार की गई।
- अग्रणी जिला प्रबंधक कार्यालयों के द्वारा तैयार इन "वार्षिक ऋण योजनाओं" को सभी जिलों का DLCC के बैठक में प्रस्तुत किया गया एवं DLCC के द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत "वार्षिक ऋण योजनाओं" को जिला स्तर पर अपनाया एवं लागू किया गया।
- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के द्वारा सभी जिलों से प्राप्त "वार्षिक ऋण योजनाओं" को संकलित कर राज्य की "वार्षिक ऋण योजना" बनाई गयी, जिसकी सारांश निम्नवर्णित है।
- सभी जिलों से प्राप्त "वार्षिक ऋण योजनाओं" के आधार पर राज्य के सभी बैंक एवं जिलों का "वार्षिक ऋण योजना संलग्न है,
- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की कृषि उप-समिति के निर्णयानुसार "वार्षिक ऋण योजना" में कृषि के sub-sector का जिलावार लक्ष्य संलग्न है।

(Amt.in Crores)

PRIORITY SECTOR ADVANCES ↓							
Agriculture			MSME				Education (up to 10 Lacs)
Crop Loan	Agri.Term Loan	Total	MICRO	SMALL	MEDIUM	TOTAL	
4182.53	3173.88	7356.41	3914.72	1542.10	1070.14	6526.96	849.56
Housing	OPS	Total Priority Sector					17245.10
1590.39	921.78						
NON-PRIORITY SECTOR ADVANCES ↓							
Heavy Industries	Education	Housing	Others	Total Non-Priority Sector			
1930.06	565.87	810.57	7055.17	10361.67			
TOTAL ADVANCES =						27606.77	

कार्यसूची सं.	5
बैठक का दिनांक	11.05.16
बैठक संख्या	55

5. REVIEW OF LENDING ऋण की समीक्षा

5.1. कृषि एवं किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें केसीसी योजना भी शामिल है

राज्य में सभी बैंकों का कुल कृषि साख रू. 12858.56 करोड़ है जो सकल ऋण का 18.18 % है। यह राष्ट्रीय मानक बेंचमार्क 18 प्रतिशत से अधिक है। सभी हितधारकों-राज्य सरकार, बैंक, नाबार्ड और अन्य एजेन्सी इस ओर फोकस होने के कारण इस क्षेत्र में संतोषजनक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।

झारखण्ड में के सी सी की स्थिति STATUS OF KCC IN JHARKHAND

(Amt. In Crores)

Type Of Banks	बैंको की श्रेणी	Disbursement During 15-16		Outstanding In KCC Accounts AS OF 31.03.16		Out of Total K.C.C at the end of Reporting Quarter (Standard Asset)	
		A/C	Amt.	A/C	Amt.	A/C	Amt.
PSB	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	385645	1048.68	1177635	3822.55	847177	3015.11
Pvt. Banks	निजी बैंक	8887	75.66	9577	73.65	9219	67.13
Total	कुल	394532	1124.34	1187212	3896.20	856396	3082.24
RRB	आर आर बी	169238	458.94	338288	1054.51	101535	306.94
Coop.Banks	काँपरेटिव बैंक	1705	3.02	13908	30.49	0	0
Total	कुल I	565475	1586.30	1539408	4981.20	957931	3389.18

रुपे क्रेडिट कार्ड RuPay Credit Card

सभी सामान्य के सी सी खातों को दि : 31.03.2013 तक Smart K.C.C खातों में परिवर्तित कर उन खातों में आवश्यक तौर पर Rupay Card जारी कर देना था ,ताकि यह ए टी एम एवं पी ओ एस में भी कार्य कर सके। यह पाया गया है कि समस्त के सी सी धारकों को एक या अन्य कारणों से रुपे कार्ड जारी नहीं किया गया है। अब तक कुल 563993 रुपे कार्ड जारी किए गए हैं। (विवरण अनुलग्नक में संलग्न है) । राज्य के सभी बैंकों के द्वारा Rupay Card जारी करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए शिविर लगाए गए पर KCC खातों में आवश्यक संख्या में आवेदन न प्राप्त होने के कारण यह लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जा सका ।

“प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना”

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” का लोकार्पण किया गया है । इस योजना के तहत ऋणी एवं अऋणी किसानों को विभिन्न कारणों से होने वाले फसल-क्षति के समय एक व्यापक बीमा-कभर प्रदान किया जाता है । झारखण्ड राज्य में भी इस योजना का शुभारम्भ किया जा चुका है । विस्तृत जानकारी के लिए इस विषय पर संलग्न SALIENT FEATURES का अवलोकन करें । झारखण्ड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 16-17 के लिए झारखण्ड राज्य की नोडल बीमा कंपनी के रूप में AGRICULTURE INSURANCE CO को अनुबंधित किया गया है । AGRICULTURE INSURANCE CO के क्षेत्रीय प्रबन्धक से आग्रह है कि वे इस विषय पर एक लघु PPT प्रस्तुत करें ।

5.2. (क) सुक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यमों का बित्त पोषण

5.2.1. सुक्ष्म एवं लघु उद्यमों का बित्त पोषण (एम एस ई) (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र) (Accounts in Lacs) (Amt. in crore)

Sl. No.	Particular		Outstanding position as at the end of		
			MARCH'2015	MARCH'2016	
(1)	(2)		(3)	(4)	
1	Micro Enterprises		Accounts	2.32	3.92
			Amount	6720.24	8989.25
	a.	Manufacturing Sector	Accounts	0.46	0.50
			Amount	1548.45	1847.90
	b.	Service Sector	Accounts	1.86	3.42
			Amount	5171.79	7141.35
2	Small Enterprises		Accounts	0.89	0.84
			Amount	6400.25	7469.67
	a.	Manufacturing Sector	Accounts	0.22	0.24
			Amount	3072.63	3042.26
	b.	Service Sector	Accounts	0.67	0.60
			Amount	3327.62	4427.41
3	Total Micro and Small Enterprises (MSE sector)		Accounts	3.21	4.76
			Amount	13120.49	16458.92
4.	MEDIUM ENTERPRISES				
a.	Manufacturing Sector		Accounts	0.25	0.03
			Amount	911.29	1142.68
b.	Service Sector		Accounts	0.27	0.27
			Amount	523.24	668.13
c.	Total of Medium Enterprises		Accounts	0.52	0.30
			Amount	1434.53	1810.81
TOTAL MSME (PRIORITY SECTOR ADVANCES)			Accounts	3.73	5.06
			Amount	14555.02	18269.73
5.	a.	Share of Credit to Micro Enterprises in total credit to MSE sector	Percent share of amounts (stipulation :60%)	51.21	54.62
	b.	Share of credit to MSE sector in NBC/ ANBC	Percent share of amount	19.92	23.27

COVERAGE UNDER CGTMSE(Collateral Free Loans Upto RS. 1.00 Crore in MSME)

(A/C in 000,Amt.in Cr.)

MSE up to Rs. 1.00 Crore						Coverage under CGTMSE					
MANUFACTURIN G		SERVICE		TOTAL		MANUFACTURIN G		SERVICE		TOTAL	
A/C	Amt.	A/C	Amt.	A/C	A/C	A/C	Amt.	A/C	Amt.	A/C	Amt.
69	4286.43	240	8139.38	309	12425.81	17	1176.40	57	2747.72	74	3924.12

टिप्पणियां

- ✚ झारखंड में कुल एमएसई में माइक्रो सेक्टर क्रेडिट की हिस्सेदारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार 60% की बेंच मार्क के विरुद्ध दिसम्बर, 2015, में 54.62 % है।
- ✚ एम एस एम ई क्षेत्र में ऋण वितरण का राज्य में वृहत संभावना है क्योंकि यह राज्य औद्योगिक रूप से धनी होने के साथ-साथ यहां सरकारी एवं निजी क्षेत्र की कई कंपनियां संचालित है। यहां खान खनिज एवं कोयला आदि की भारी संपदा है। इनके लिए उचित एन्सियलरी उद्योग को स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। राज्य में एम एस एम ई के विकास हेतु प्रयास करना चाहिए।
- ✚ यह पाया गया है कि झारखण्ड में प्रयोग किये जाने वाले वस्तुओं का निर्यात क्रेडिट कोलकाता, मुम्बई आदि जगहों पर अवस्थित बैंक शाखाओं द्वारा किया जाता है स्थानीय शाखाओं को भी उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से निर्यात क्रेडिट हेतु सशक्त करना चाहिए।
- ✚ झारखण्ड राज्य में, 1 करोड़ की सीमा के अंदर कुल 309000 MSE ऋण खातें हैं, परंतु इनमें से केवल 74000 ऋण खातों में, यानी कि सिर्फ 24 % खातों में ही CGTMSE कवरेज लिया गया है।

5.2 (ख) “प्रधानमंत्री मुद्रा योजना”

दिनांक 8 अप्रैल, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कि गई | यह योजना मुख्यतः गैर-कृषि क्षेत्र के छोटे उद्यमियों को बैंक द्वारा वित्त पोषण के लक्ष्य से शुरू की गई है | इस योजना को ऋण-राशि के अनुसार निम्नलिखित 3 संवर्गों में विभाजित किया गया है ,

1. “शिशु” – रु. 50,000.00 तक ऋण राशि के लिए |
2. “किशोर” - रु. 5,00,000.00 तक ऋण राशि के लिए |
3. “तरुण” - रु. 10,00,000.00 तक ऋण राशि के लिए |

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में झारखण्ड की उपलब्धि (8.04.15 से 31.03.16 तक)
(सं:000 में ,राशि करोड़ में)

Shishu				Kishore				Tarun				Total Mudra Loan			
Target		Achievement		Target		Achievement		Target		Achievement		Target		Achievement	
सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि
205	410	309	446	55	1093	32	735	14	820	8	474	274	2323	349	1655

झारखण्ड राज्य में मुद्रा ऋण की विभिन्न संवर्गों में, 31 मार्च, 2016 तक किये गए सभी बैंकों के कुल संवितरण की AFY 15-16 में लक्ष्यप्राप्ति का प्रतिशत निम्नलिखित है ,

1. शिशु - 151%
2. किशोर - 58 %
3. तरुण - 57 %

AFY 15-16 में झारखण्ड राज्य में, मुद्रा ऋण की स्वीकृति/संवितरण “शिशु” संवर्ग में काफी अच्छी है परंतु “किशोर” व “तरुण” में आशानुरूप नहीं है। यद्यपि, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, SLBC, झारखण्ड, वित्त निदेशालय, झारखण्ड सरकार द्वारा विभिन्न बैठकों में इस बात पर चिंता व्यक्त किया गया एवं सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों द्वारा उन बैठकों में यह आश्वासन भी दिया गया कि उनके बैंकों में मुद्रा ऋण संवितरण में अपेक्षित गति प्रदान की जाएगी। इसके बावजूद किशोर व तरुण ऋण में स्वीकृति/संवितरण में अपेक्षित वृद्धि न होना एक गंभीर चिंता का विषय है। सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से पुनः यह आग्रह है कि, वे योजनावद्ध तरीके से मुद्रा ऋण के संवितरण में अपेक्षित गति प्रदान करें।

5.3. शिक्षा ऋण Education loan

शिक्षा ऋण योजना के तहत बैंकों का निष्पादन

(Amt. in crore)

Particulars	As on 31.03.15	As on 31.03.16				Total As on 31.03.16	GROWTH Y-O-Y IN EDU. LOAN	DISBURSEMENT MADE DURING AFY 2015-16 in ACP 15-16
		Public Sector Bank	Priv ate Sec tor Ban k	RRB	Coop. Bank			
No. of Account	62917	58993	138	944	1	60076	(-)2841	12784
Amount (In crore)	2198.84	2157.89	3.24	26.94	0.10	2188.17	(-)10.67	338.28

- उपरुक्त आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि राज्य के बैंकों के शिक्षा ऋण का संवितरण आशानुरूप नहीं है। पिछले एक साल में राज्य में बैंकों के द्वारा दिये गये कुल शिक्षा ऋण रु 10.67 करोड़ से घट गया है, यह अत्यंत चिंता की विषय है। पिछले कई SLBC बैठक में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, परंतु इसमें कोई आशानुरूप प्रगति परिलिखित नहीं हो रही है, एवं शिक्षा ऋण संवितरण में झारखण्ड राज्य के बैंकों का प्रदर्शन एक चिंता का विषय बना हुआ है। शिक्षा ऋण देश के मानव पूंजी के विकास के लिए एक निर्णायक भूमिका निभाता है। देश के भविष्य एवं आने वाली पीढ़ियों के विकास के लिए सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों को इस क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। झारखंड से प्रति वर्ष छात्र बड़ी संख्या में देश के विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक कॉलेजों में प्रवेश पा रहे हैं। राज्य के बैंकों से शिक्षा ऋण की स्वीकृति में और बेहतर भूमिका निभाने की अपेक्षा है।

- माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के द्वारा 54 वीं slbc बैठक के दौरान उपर्युक्त विषय पर एवं विशेष कर अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को शिक्षा-ऋण नहीं दिये जाने पर चिंता व्यक्त किया गया था | RBI के प्रावधानों के तहत रु. 4.00 लाख तक के शिक्षा-ऋण में किसी भी तरह के SECURITY की आवश्यकता नहीं है, इसीलिये 4 लाख तक के शिक्षा-ऋण C.N.T या S.P.T एक्ट के प्रभाव से मुक्त है, इसीलिये उन्होंने बैंकों से निर्वाध रूप से SC/ST संवर्ग के योग्य छात्रों को रु.4.00 लाख तक के शिक्षा ऋण देने का आग्रह किया |
- माननीय मुख्यमंत्री के आग्रह के अनुसार पिछले slbc बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि AFY 2016-17 की शिक्षा-सत्र में एक CAMPAIGN के द्वारा SC/ST छात्रों को रु.4.00

लाख तक के शिक्षा-ऋण की स्वीकृति दी जाएगी एवं राज्य के सभी बैंक इस कैम्पेन में भाग लेंगे |

- राज्य के सभी बैंकों के द्वारा निम्नलिखित तरीकों से यह CAMPAIGN चलाया जाएगा,
 - i. इस campaign में वर्तमान में रु.4.00 लाख तक शिक्षा-ऋण प्राप्त अनुसूचित-जाति के छात्रों के संख्या के दोगुना छात्रों को रु.4.00 लाख तक शिक्षा-ऋण स्वीकृत करने की लक्ष्य रखा गया है |
 - ii. राज्य के विभिन्न शिक्षा-संस्थानों में शिक्षा ऋण संवितरण हेतु विशेष शिविरों का आयोजन.
 - iii. SLBC के द्वारा नये शिक्षा-ऋण संवितरण का बैंक वार लक्ष्य प्रदान एवं गहन MONITORING.
 - iv. सभी जिला स्तर पर LDM व DLCC के द्वारा शिक्षा ऋण से संबंधित विशेष बैठक का आयोजन एवं जिला स्तर पर क्लोज मोनिटरिंग.
- आज का इस 55वीं SLBC बैठक में, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इस CAMPAIGN की शुभारंभ किया गया, एवं 25 SC/ST छात्रों को शिक्षा-ऋण वितरित किया गया |
- हाल ही में भारत सरकार के द्वारा Credit Guarantee Fund for Skill Development (CGFSSD) की शुरुआत की गई, इस योजना के तहत कोशल विकास हेतु लिए गए शिक्षा ऋण में गारंटी कवर प्रदान की जाएगी |

5.4- आवास ऋण

Performance of Banks under Housing loan Scheme

आवास ऋण योजना के तहत बैंकों के प्रदर्शन

(Amt.in Crore करोड़ में राशि)

Particulars	Up to 31.03.15	31.03.2016				Total Up to 31.03.16	Y-to-Y INCRE ASE	Disburse ments made in ACP 15-16
		Public Sector Banks	Private Sector Banks	RRB	Coop. Banks			
No. of Account खाता की सं.	65221	61667	5230	542	20	67459	5792	16427
Amount राशि(In croreकरोड़ में)	4520.02	4836.64	453.54	35.76	2.86	5328.80	492.16	1642.85

**5.5 CREDIT FLOW TO SPECIAL CATEGORY OF
BORROWER (ऋण लेने वालों की विशेष श्रेणी हेतु ऋण प्रवाह)**

5.5.1 अल्पसंख्यक समुदायों हेतु ऋण प्रवाह

31 मार्च, 2016 तक स्थिति निम्न है:
(Rs. In Crores)

31 March, 2015		% Share	31 March, 2016		% Share
P.S.A	Loans to Minority Community		P.S.A	Loans to Minority Community	
33736.06	4869.83	14.43	38803.93	5291.94	13.63

5.5.2 महिलाओं के लिए ऋण प्रवाह

31 मार्च, 2016 की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है (रु.करोड़ में)

31 March, 2015		PERCENTAGE OF CREDIT TO WOMEN	31 March, 2016		PERCENTAGE OF CREDIT TO WOMEN
Gross Credit	Of which to Women		Gross Credit	Of which to Women	
65842.38	13200.37	20.04	70728.48	16236.82	22.95

5.5.3 डीआरआई के लिए ऋण प्रवाह(

31 मार्च, 2016 को इस क्षेत्र में बैंकों के प्रदर्शन, नीचे इस प्रकार है:

(Rs. in Crore करोड़ में रू .)

31 March, 2015		31 March, 2016		DRI Percentage in Net Credit
Net Credit	DRI	Net Credit	DRI	
65842.38	29.55	70728.48	38.66	0.05

SC/ST के लिए ऋण प्रवाह

31 मार्च, 2016 समाप्त तिमाही में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लिए ऋण प्रवाह की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है- :

(करोड़ में रू.)

31 March, 2015		Percent age In Net-Credit	31 March, 2016		Percent age In Net-Credit
Net Credit	Loans to SC/ST		Net Credit	Loans to SC/ST	
65842.38	10716.41	16.27	70728.48	13142.01	18.58

5.6. Scheme for financing of Women SHG

एसएचजी महिलाओं के वित्तपोषण हेतु योजना

31 मार्च, 2016 तक झारखंड राज्य के एल.डब्ल्यू.ई प्रभावित जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों की प्रगति निम्नानुसार है,

(रु करोड़ में)

जिलों की संख्या	18
ब्लाकों की संख्या	270
गैर सरकारी संगठन की संख्या	127
नवगठित डब्ल्यू.एस.एच.जी की संख्या	42582
एसएचजी बचत लिंकड की संख्या	32949
एसएचजी ऋण लिंकड की संख्या	13854

5.7. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

एन आर एल एम की उपलब्धि (31 मार्च, 2016 तक)

31 मार्च, 2016 तक की गई मुख्य प्रगति - संचयी और वार्षिक
में)

(रु लाख)

संकेतक Indicators	Status as on March'15	उपलब्धि Achievement in AFY-15-16	Cumulative achievement till date since Inception
No of Blocks	40	40	80
No of Villages	2312	1291	3603
Total No of SHGs supported By SRLM	16945	10548	27493
Total families supported by SRLM	211424	83365	294789
No of SHG receiving R.F	11119	8461	19580
Amt. of RF disbursed in Lakhs	1666.20	1260.80	2927
No of SHG receiving CIF	7458	8270	15728
Amt. of CIF disbursed in Lakhs	3783.18	5764.41	9547.59
No of SHG credit linked with Banks	1841	6745	8586
Amt. of Credit availed from Banks (in Lacs)	1014.50	3597	4611.50

एजेंडा सं.	6
बैठक की तिथि	11.05.16
बैठक की संख्या	55

**वित्तीय समावेशन
एवं
प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)**

झारखंड में प्रधानमंत्री जन धन योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति

A. बी.सी (बैंक मित्र) द्वारा एसएसए के कवरेज की स्थिति

एसएसए की कुल संख्या	बी.सी द्वारा एसएसए का कवर (Fixed Location)	बैंक शाखा द्वारा एसएसए कवर	अनकवर्ड
4175	2693	584	898

B. पीएमजेडीवाई के तहत खोले गए बीएसबीडी खातों की स्थिति ।

31.03.16 तक खोले गए बीएसबीडी खातों की संख्या			PMJDY खातों मे जारी किये गये कुल रूपे कार्ड की संख्या	आधार Seeding किये गये PMJDY खातों की संख्या
ग्रामीण	शहरी	कुल		
4392510	1703959	6096469	5080084	4187606

“ प्रधानमंत्री मंत्री जन-धन योजना ”(PMJDY) में ध्यानाकर्षण योग्य बिंदु ,

- हाल में वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार के द्वारा सभी SSA में बैंक-मित्र की मौजूदगी के बारे में सर्वेक्षण की गयी और इनमे पाया गया वर्तमान में 898 SSA में कोई भी बैंक मित्र कार्यरत नहीं है, वें या तो अपने कार्य को छोड़ चुके हैं या अधिकतर अपने कार्य क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहते हैं | SLBC के पास इन SSA का सूची उपलब्ध है, सभी बैंकों के नियंत्रक-प्रमुखों से आग्रह है की वें अपने बैंकों के आवंटन के अनुसार इन जगहों पर अविलम्ब बैंक-मित्र की मौजूदगी सुनिश्चित करें

2. मिशन डायरेक्टर, PMJDY द्वारा इस बात पर चिंता प्रकट किया गया और दिनांक : 28.07.15 को बुलाई गई एक बैठक में, जिसमें सभी मुख्य बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित थे, यह निर्णय लिया गया कि
 - i. सभी SSA में पदस्थापित, बैंक-मित्रों का सुचारू संचालन के जिम्मेदारी, आवंटित बैंक की नियंत्रक कार्यालय की होगी।
 - ii. नियंत्रक कार्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि - प्रतिदिन प्रति बैंक मित्रों के औसत लेन-देन की संख्या न्यूनतम 50 हो।
 - iii. सभी बैंकों के नियंत्रक कार्यालय, प्रतिमाह सभी बैंक मित्रों का लेन-देन का ब्यौरा, निहित प्रपत्र में, जो की सभी बैंकों को उपलब्ध करवाया जा चुका है, DBT सेल, झारखंड सरकार को, उपलब्ध करेंगे।
 - iv. सभी बैंक शाखाओं के शाखा प्रबंधक, प्रति माह, अपने शाखा से संबंधित बैंक-मित्रों का निरीक्षण के उपरांत निहित प्रपत्रों में नियंत्रक कार्यालय को निरीक्षण-रिपोर्ट जमा करेंगे।
 - v. उपरुक्त निरीक्षण-रिपोर्ट के एक प्रति BLBC को शाखा द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके आधार पर BLBC बैंक मित्रों के कार्यों का Monitoring करेगी।
 - vi. सभी बैंक शाखाओं में, ग्राहकों को बैंक मित्रों से लेन-देन हेतु प्रेरित करने के लिए एक सूचना प्रदर्शित की जाएगी।
3. पीएमजीडीवाई योजना के तहत खोला गया कुछ खातों में अब तक पास-बुक जारी नहीं किए गए हैं, सभी बैंको से यह आग्रह है की वे जल्द से जल्द सभी खातों में पास-बुक जारी करना सुनिश्चित करें।
4. यद्यपि पीएमजीडीवाई योजना के तहत खोला गए खातों में अब तक कुल 5080084 रुपये कार्ड जारी किए गए, परन्तु निरीक्षण के दौरान यह पता चल रहा है की बहुत से रुपये कार्ड अब तक अवितरित है एवं 1940456 रुपये कार्ड अब तक Activated नहीं किया गए।

“प्रधानमंत्री जन-धन योजना” के द्वितीय चरण में, जन सुरक्षा हेतु, लागू किया गया, विभिन्न बीमा एवं पेन्शन योजनाएं :

दिनांक : 9.05.15 को राष्ट्र के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित योजनाएं लागू की गई,

1. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना.
2. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना.
3. अटल पेन्शन योजना.

दिनांक: 31.12.15 तक इन योजनाओं में सभी बैंकों की उपलब्धि निम्नवर्णित है,

PMJJBY		PMSBY		APY	
Total Enrolments	Premium Received By Auto Debit	Total Enrolments	Premium Received By Auto Debit	Total Enrolments	Premium Received By Auto

					Debit
460785	377379	1649586	1388783	38853	38751

वित्तीय समावेशन एवं BRANCH EXPANSION पर भारतीय रिज़र्व बैंक का अद्यतन दिशानिर्देश

- भारतीय रिज़र्व बैंक के अद्यतन निर्देशानुसार 5000 से ज्यादा आवादी वाले सभी गाँवों में दिनांक :31.03.17 तक बैंक की शाखा खोलना अनिवार्य है | झारखण्ड राज्य में ऐसे 259 गाँवों को चिन्हित किया गया एवं पाया गया कि इनमे से 122 गाँवों में ही बैंक की शाखा मौजूद है, बाकी के 137 गाँवों को विभिन्न बैंकों को आवंटित कर उन्हें सूचित किया गया |
- इस मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक के रोड मैप के अनुसार इनमे से 31 गाँवों में बैंकों के द्वारा जनवरी-मार्च,16 तिमाही में शाखा खोलना अनिवार्य था, पर विभिन्न कारणों के चलते यह गाँवों में शाखा नहीं खोला गया | सभी बैंकों के नियंत्रकों से आग्रह है कि SLBC द्वारा उनको भेजा गया आवंटन-सूची के अनुसार, इस योजना के तहत बनाया गया ROAD MAP के अनुसार सभी गाँवों में बैंक शाखा का संचालन आरंभ करें |

कार्यसूची सं	7
बैठक का दिनांक	11.05.16
बैठक सं	55

एन पी ए & वसूली - एन पी ए/ बैंकों के स्ट्रेस्ड आस्तियों के रुकाव हेतु नियंत्रक उपाय एवं वसूली से संबंधित उपाय

गैर निष्पादनीय आस्तियां

राज्य के बैंकों में दी 31 मार्च, 2016 को एन पी ए की स्थिति निम्नवत है :-

[राशि करोड़ में]

विवरण	31.03.15	31.03.16	Y-TO-Y Growth	% Growth
<i>Net Credit</i>	65842.38	70728.48	4886.10	7.42 %
Net N.P.A	3680.70	4597.98	917.28	24.92 %
Percentage of N.P.A	5.59 %	6.50 %	0.91 %	

नोट : उपरोक्त राशि में रिटेन ऑफ (Written-Off) की राशि शामिल नहीं है।

- झारखंड राज्य में बैंकों की गैर निष्पादनीय अस्ति (N.P.A) , एक चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुकी है |वर्ष-दर-वर्ष NPA में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है ,जो सकल अग्रिम की वृद्धि की गति से तेज है | रु 4597.98 करोड़ का NPA, जो सकल अग्रिम का 6.50 % है , एक चिंताजनक आंकड़ा है एवं RBI द्वारा निर्धारित मानक से काफी ज्यादा है |
- ज्यादा NPA बैंकों से नए ऋण-संवितरण में प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है एवं राज्य के अंदर नए ऋण की स्वीकृति में एक शंका के वातावरण का कारण बन रही है।
- NPA एवं उससे संबंधित PROVISIONING बैंकों की CAPITAL BASE पर प्रतिकूल असर डाल रही है |
- RBI, सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुख, केन्द्रीय एवं राज्य सरकार को मिलकर इस समस्या की एक कारगर निदान निकालने की आवश्यकता है , बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागीओं से इस विषय पर चर्चा एवं सुझाव का अनुरोध किया जा रहा है |

सर्टिफिकेट केस का स्थिति

राज्य के बैंकों में सर्टिफिकेट केस के लंबित मामलों की स्थिति इस प्रकार है:

[राशि करोड़ में]

Type of Bank	31.03.15		31.03.16	
	सं	राशि	संख्या	राशि
Commercial Bank	106211	372.70	106628	415.80
R.R.B	6222	14.99	6520	27.81
Total	112433	387.70	113148	443.61

सर्टिफिकेट केस की तिमाही निपटान की स्थिति निम्नवत है

[राशि करोड़ में]

बैंक	31.12.15	
	संख्या	राशि
Commercial Bank	288	428.43
R.R.B	1022	13.57
Total	1310	452.00
	कुल 113148 मामलों में से	

DRT केस की स्थिति

दिनांक 31 मार्च, 2016 तक बैंकों के डी आर टी केसों की स्थिति इस प्रकार है :-

[राशि करोड़ में]

Status as Of 31.03.15		Cases Filed during March,16 Quarter		Cases Resolved during March,16 Quarter		Status as Of 31.03.16	
सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि
1896	633.61	115	54.90	38	8.54	2262	820.02

कार्यसूची सं	8
बैठक का दिनांक	11.05.16
बैठक सं	55

31.03.16 को सरकारी प्रायोजित कार्यक्रम

8.1 प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

दिनांक 31 MARCH, 2016 तक समग्र स्थिति

(राशि करोड़ में)

Target	Applications received	Applications sanctioned		Applications Disbursed		REJECTED	Pending
		3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
1913	2632	1396	61.41	1138	40.71	344	884

- ✚ वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए सबसिडी प्राप्त करने की तिथि 31.05.2015 तक बढ़ा दिया गया था। इसके कारण से वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान का प्राप्त कुछ आवेदनों को वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान स्वीकृत किया गया है।
- ✚ पीएमईजीपी के तहत आवेदनों का ई-ट्रैकिंग के लिए प्रस्तावित सेवाएँ अधिकांश बैंकों के द्वारा अपने वेबसाइट पर समाविष्ट नहीं किया है। बैंकों को अपने प्रधान कार्यालय से संपर्क कर इस सेवा की शुरुआत करनी चाहिए।

कार्यक्रम संख्या	9
बैठक की तारीख	11.05.16
बैठक संख्या	55

10. RSETI & FLC का परिचालन

झारखंड राज्य में आरसेटी की वर्तमान स्थिति निम्नांकित है :

(as of 30.09.15)

झारखंड राज्य के 24 जिलों में निम्नलिखित सूची के अनुसार, विभिन्न बैंको के द्वारा 24 आरसेटी और 1 रुडसेटी संचालित किया जा रहा हैं |

बैंक ऑफ इंडिया	-	11 जिले
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	-	8 जिले
इलाहाबाद बैंक	-	3 जिले
पंजाब नेशनल बैंक	-	2 जिले
कुल		24 जिले

एवं रुडसेटी (रांची जिले की सिल्ली में केनरा एवं सिंडिकेट बैंक द्वारा संचालित) 1 जिला

- स्वतंत्र निदेशकों की पोस्टिंग :
स्वतंत्र निदेशकों पदभार ग्रहण किया 25 केन्द्रों में
- आरसेटी के लिए परिसर की स्थिति निम्न है :
किराए के परिसर 7 केन्द्रों में
सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी परिसर (अस्थायी) 18 केन्द्रों में
- भूमि आवंटन की स्थिति
भूमि आवंटित 25 केन्द्रों में
- भूमि स्थानांतरण की स्थिति
भूमि स्थानांतरित- 25
- एम.ओ.आर.डी. दावा प्राप्ति की स्थिति : 21

निदेशकों का प्रशिक्षण:

निदेशकों की संख्या जिन्होंने टीटीपी प्रशिक्षण प्राप्त किया 22 निदेशक

निदेशकों की संख्या जिन्होंने टीटीपी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया - 3 निदेशक

AFY 14-15 का वार्षिक लक्ष्य :

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की संख्या - 676

Trainees की संख्या - 20160

AFY 14-15 के दौरान दिसम्बर, 2015 तक आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम :

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की संख्या - 673
Trainees की संख्या - 20179

RSETI भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति ,
भवन निर्माण कार्य सम्पूर्ण - 1
भवन निर्माण कार्य प्रगति पर - 11

RSETI प्रशिक्षार्थियों की बैंकों से वित्तीय संबन्धता (CREDIT LINKAGE) की स्थिति :

AFY 2014-15 के दौरान		AFY 2015-16 के दौरान	
कुल प्रशिक्षार्थी	बैंकों से वित्तीय संबन्धता स्थापित	कुल प्रशिक्षार्थी	बैंकों से वित्तीय संबन्धता स्थापित
15978	1532	20179	1530

नोट :

51वीं SLBC बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सभी इच्छुक RSETI प्रशिक्षार्थियों को अनिवार्य रूप से, उनके सेवा क्षेत्र के बैंक शाखाओं के द्वारा CREDIT LINKAGE स्थापित की जाएगी | RSETI निदेशकों के द्वारा बैंकों की संबंधित शाखाओं में आवेदन भेजे जाएंगे एवं आवेदनों की अस्वीकृति के अधिकार, केवल नियंत्रक कार्यालयों के पास ही रहेंगे | परंतु उपरोक्त आंकड़ों से यह प्रतीत होता है कि यह दिशा में कार्यवाही शुरू हो चुकी है, परंतु उपलब्धि आशाजनक नहीं है, SPC , RSETI से यह आग्रह है की वें , इस विषय की MONITORING करें एवं अगर बैंक शाखाओं के द्वारा SLBC की उपरुक्त निर्णय का अनुपालन नहीं हो रहा है, तो उन शाखाओं का जिलावार व बैंकवार सूची SLBC को उपलब्ध कराएँ , ताकि संबंधित नियंत्रकों से इस मुद्दे का निष्पादन करवाया जा सके |

वित्तीय साक्षरता केंद्र का संचालन

आर.बी.आई के निर्देशानुसार , विभिन्न जिला स्तर पर संचालित सभी अग्रणी बैंकों को प्रत्येक LDM कार्यालयों में, समयबद्ध ढंग से एक वित्तीय साक्षरता केन्द्र का स्तापना करना अनिवार्य है | आर.बी.आई द्वारा यह निर्देश भी दिया गया की सभी बैंको के ग्रामीण शाखाओं को आवश्यक तौर पर F.L.C Camp का आयोजन करना है। इसके अलावा बैंक दूसरों स्थानों पर भी आवश्यकता आधारित वित्तीय साक्षरता केन्द्रों की स्थापना पर विचार कर सकते हैं | वर्तमान में 19 वित्तीय साक्षरता केन्द्र (FLCs) झारखंड के राज्य में परिचालन कर रहे हैं :

बैंक का नाम	बैंक वित्तीय साक्षरता केन्द्र (जिला स्तर पर)	परिचालन	संख्या
बीओआई	रांची, गुमला, लोहरदगा, सिंहभूम गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़	(प) एवं (पु)	10
एसबीआई	देवघर, पाकुर, साहिबगंज, जामताड़ा, गढ़वा, लातेहर, पलामू		7
इलाहाबाद बैंक	दुमका व गोड्डा		2

उपरोक्त बैंको के अलावा निम्नलिखित ग्रामीण बैंको के द्वारा भी वित्तीय साक्षरता केन्द्र का सञ्चालन किया जाता है,

झारखण्ड ग्रामीण बैंक - 16 केन्द्र

वनांचल ग्रामीण बैंक - 9 केन्द्र

मार्च, 2016 तिमाही के दौरान आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर

मार्च तिमाही में आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर की संख्या	
वित्तीय साक्षरता केन्द्र द्वारा	336
ग्रामीण शाखाओं द्वारा	1938
कुल	2274

वर्तमान में वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार के द्वारा सभी I.T.I (सरकारी एवं गैर सरकारी) एवं VOCATIONAL TRAINING CENTER के प्रशिक्षणार्थियों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने हेतु, व्यापक पैमाने पर एक परियोजना शुरू किया गया, जिसके तहत सभी बैंक शाखाओं एवं FLC केन्द्रों को I.T.I (सरकारी एवं गैर सरकारी) एवं VOCATIONAL TRAINING CENTER आवंटित किया गया। उन शाखाओं एवं FLC केन्द्रों को अपनी अपनी आवंटित संस्थाओं में संचालित सभी सत्रों में नियमित रूप से वित्तीय साक्षरता प्रदान करना पड़ेगा। सभी नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह है कि वे इस विषय पर अपने बैंक की शाखा एवं FLC केन्द्रों को सूचित करें एवं नियमित रूप से इस विषय पर MONITORING करें।

कार्यक्रम सं	10
बैठक की तारीख	11.05.16
बैठक संख्या	55

एसएलबीसी के विभिन्न उप समितियों के कामकाज

पहले के एसएलबीसी की बैठकों में लिए गए निर्णय के संदर्भ में, एसएलबीसी के निम्नलिखित उप-समितियां कार्य कर रहे हैं। पिछली बैठक की स्थिति नीचे दी गई है:

एस.एल.बी.सी की उप समितियां :

S N	उप समिति के नाम	उप समिति के अध्यक्ष	उप समिति के अन्य सदस्यों में	संदर्भ की शर्तें	पिछली बैठक की तिथि
1.	कृषि तथा संबद्ध उप समिति	प्रमुख सचिव / (कृषि) सचिव GOJ संयोजक – नाबार्ड	1. प्रमुख सचिव सचिव / संस्थागत वित्त 2. प्रमुख सचिव सचिव /, जल संसाधन विभाग। 3. सचिव, वन विभाग। 4. नाबार्ड प्रमुख महाप्रबंधक या डीजीएम के स्तर के बराबर 5 (संयोजक बैंक एसएलबीसी) आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 6) एसबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 7) बीओआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 8) कोई भी दो प्रमुख बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 9) रजिस्ट्रार सहकारी समितियां	1) कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां, केसीसी सहित 2) नई परियोजना/स्कीम 3) ऋण देने के लिए क्षमता का विकास	03.05.16

2.	निर्यात संवर्धन	एसएलबीसी के संयोजक बैंक - संयोजक एसएलबीसी	<p>1). प्रमुख सचिव सचिव / संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ</p> <p>2 (भारतीय रिजर्व बैंक)विदेशी मुद्रा विभाग. एजीएम(</p> <p>3) स्थानीय निर्यात संस्था</p> <p>4)उद्योग विभाग</p> <p>5 (एक्विजम बैंक</p> <p>6)अन्य सदस्य बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई, और पीएनबी</p>	<p>1) निर्यात क्रेडिट के तहत ऋण देने की प्रगति की समीक्षा 2)कृषि हस्तकला /के निर्यात में सुधार के लिए सुझाव 3) निर्यात संवर्धन के लिए सक्षम कारक</p>	20.01.16
3.	सुरक्षा	प्रमुख सचिव / सचिव (गृह), GOJ संयोजक- एसबीआई	<p>1) प्रमुख सचिव सचिव / गृह विभाग</p> <p>2) एडीजी / पुलिस महानिरीक्षक – परिचालन</p> <p>3) प्रमुख सचिव सचिव / संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ</p> <p>4) आरबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि)</p> <p>5) संयोजक बैंक एसएलबीसी) आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि)</p> <p>6) एसबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि</p> <p>7) बीओआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि)</p> <p>8) कोई भी दो प्रमुख बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि)</p> <p>9) झारखंड ग्रामीण बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि)</p>	<p>1) बैंक के ट्रेजरी की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा</p> <p>2) राज्य की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के बारे नक्सल क्षेत्र में विशेष रूप से चर्चा करें</p> <p>3) बैंक डकैती के मामलों में अंतिम रिपोर्ट</p> <p>4) बैंक शाखाओं /करेंसी चेस्ट में पुलिस बल की तैनाती</p>	29.04.16

4.	सीडी अनुपात और एसीपी उप-समिति	एसएलबीसी के संयोजक बैंक संयोजक - एसएलबीसी	1) प्रमुख सचिव सचिव / संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ. 2) भारतीय रिजर्व बैंक 3) नाबार्ड 4) बैंक स्टेट भारतीय () 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) पंजाब नेशनल बैंक 7) झारखंड ग्रामीण बैंक 8) केनरा बैंक 9) (यूनियन बैंक	1) एसीपी की निगरानी उपलब्धि एवं अनुमानित सीडी अनुपात 2) खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के लिए विशेष रणनीति 3) एसीपी के तहत ऋण देने में वृद्धि के लिए कारकों को सक्षम करने का विकास	20.01.16
5.	एसएलबीसी परिचालन समिति	एसएलबीसी के संयोजक बैंक संयोजक - एसएलबीसी	1) संस्थागत वित्त विभाग 2) भारतीय रिजर्व बैंक 3) नाबार्ड 4) निदेशक, उद्योग 5) आईसीआईसीआई बैंक 6) केनरा बैंक 7) पंजाब नेशनल बैंक 8) बैंक ऑफ इंडिया 9) भारतीय स्टेट बैंक	1) नवीनतम स्थिति और सरकार के पास लंबित मुद्दें बैंक / । 2) एसएलबीसी कामकाज में सुधार) बैंक / सरकार)	20.01.16
6.	विधानमंडल और अन्य मुद्दे पर उप समिति	सचिव, संस्थागत वित्त संयोजक- एसएलबीसी	1) सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, सहकारी 3) सचिव, राजस्व 4) सचिव, कृषि 5) सचिव, योजना 6) भारतीय स्टेट बैंक 7) बैंक ऑफ इंडिया 8) इलाहाबाद बैंक 9) भारतीय रिजर्व बैंक	विधानमंडल से संबंधित सभी मुद्दों पर, राज्य में ऋण के माध्यम से विकास के लिए संशोधन और अन्य गतिविधियों के लिए राज्य सरकार से प्राप्त किया।	02.02.15
7.	एमएसएमई और सरकार पर उप-समिति, प्रायोजित योजनाएं	सचिव) ग्रामीण विकास (संयोजक- बीओआई	1) सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, संस्थागत वित्त 3) सचिव, उद्योग 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) इलाहाबाद बैंक	सरकार के तहत प्रायोजित योजनाओं में एमएसएमई वित्तपोषण और वित्तपोषण से संबंधित सभी मुद्दे,	30.12.15 को RBI Empowered Com.on MSME की बैठक बुलाया गया था
8	आवास वित्त पर उप-समिति	सचिव) शहरी विकास) संयोजक- एसबीआई	1) सचिव, शहरी विकास 2) सचिव, संस्थागत वित्त 3) राष्ट्रीय आवास बैंक के	आवास वित्त पोषण से संबंधित सभी मुद्दें) शहरी	07.08.15

			प्रतिनिधि 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) इलाहाबाद बैंक 7) दोनों ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष	एवं ग्रामीण क्षेत्र(	
9	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर उप-समिति	सचिव)ग्रामीण विकास(संयोजक - झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी	1) प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, आईएफ और पीआई, GoJ 3) भारतीय रिजर्व बैंक 4) एसएलबीसी 5) भारतीय स्टेट बैंक 6) बैंक ऑफ इंडिया 7) केनरा बैंक 8)पी.एन.बी. 9)जे.जी.बी. 10) नाबार्ड	आजीविका संवर्धन रणनीतियों पर राज्य स्तर समर्थन- झारखंड	10.08.15

कार्यक्रम सं.	11
बैठक की तिथि	11.05.16
बैठक सं.	55

विविध कार्यसूची

- राज्य के 48 वित्तीय साक्षरता केन्द्रों में से 9 केन्द्रों में विगत तिमाही में एक भी वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन नहीं किया गया | यह केंद्र झारखण्ड ग्रामीण बैंक - 9 केंद्र, वनांचल ग्रामीण बैंक- 2 केंद्र एवं SBI- 1 केंद्र, द्वारा संचालित है | इन बैंकों से आग्रह है की वे तुरंत इन केन्द्रों में वित्तीय साक्षरता शिविर का संचालन आरम्भ करें | राज्य के अन्य बैंकों के ग्रामीण शाखाओं के द्वारा संचालित वित्तीय साक्षरता शिविर एवं FLC COORDINATORS एवं बैंक शाखाओं को आवंटित कौशल विकास केंद्र एवं स्कूलों में संचालित वित्तीय साक्षरता सत्रों का संख्या भी आशानुरूप नहीं है | सभी नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह है की वे वित्तीय साक्षरता से संबंधित शिविर एवं सत्रों का नियमित रूप से आयोजन सुनिश्चित करें |

(प्रस्तावक - भारतीय रिज़र्व बैंक)

- GREEN KISAN CREDIT CARD योजना के द्वारा गुजरात के डांग जिले में आदिवासियों को पेड़ों पर सरल MICRO CREDIT उपलब्ध करायी जा रही है | चूंकि झारखण्ड राज्य में भी आदिवासी जनसंख्या एवं प्राकृतिक वनसंपदा का बहुतायत में है इसलिये इस योजना को झारखंड राज्य में भी सफल रूप से संचालित किया जा सकता है | इस योजना के विस्तृत जानकारी संलग्न है, भारतीय रिज़र्व बैंक के उपस्थित प्रतिनिधि से आग्रह है कि वे इस योजना पर प्रकाश डालें |

(प्रस्तावक - भारतीय रिज़र्व बैंक)

- राज्य के सहकारी बैंकों का ANNUAL CREDIT प्लान 2015-16 में दिये गये लक्ष्य-प्राप्ति संतोषजनक नहीं है | सहकारी बैंक के उपस्थित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से आग्रह है वे इस वित्तीय वर्ष में लक्ष्य प्राप्ति में सुधार हेतु उपयुक्त कार्ययोजना के बारे में इस बैठक में चर्चा करें एवं SLBC को सूचित करें |

(प्रस्तावक- कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार)

- झारखण्ड राज्य में JOINT LIABILITY GROUP के तहत दिये गए ऋण की प्रगति आशानुरूप नहीं है | SLBC से आग्रह है कि वे AFY 2015-16 में सभी बैंक एवं जिलों को JOINT LIABILITY GROUP के तहत वित्त-पोषण का लक्ष्य प्रदान करें एवं बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह है कि वे इस लक्ष्य प्राप्ति को सुनिश्चित करें |

(प्रस्तावक : नाबार्ड)

- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की कृषि उप समिति के दिनांक: 3.05.16 को आयोजित बैठक में झारखण्ड सरकार के द्वारा रु 1.00 लाख से अधिक कृषि-ऋण पर आवश्यक रूप से लिए जाने वाले भूमि बंधक /COLLATERAL सिक्क्यूरिटी के बदले उन ऋण खातों में राज्य सरकार की गारंटी लिए जाने की प्रस्ताव दिया गया है | वीतीय सेवा विभाग, भारत सरकार ,भारतीय रिज़र्व बैंक, नाबार्ड एवं सभी बैंकों के उपस्थित नियंत्रक प्रमुखों को इस विषय पर उपयुक्त निर्णय लेने की आग्रह किया जाता है |

(प्रस्तावक- कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार)

- ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार एवं JSLPS के द्वारा आग्रह किया गया कि PMJDY कार्यक्रम के तहत संचालित "बैंक-मित्र" केन्द्रों में राज्य के महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को पदस्थापित किया जाय | उपस्थित सभी STAKE HOLDERS से आग्रह है कि इस विषय में उपयुक्त निर्णय लें |

(प्रस्तावक : ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार एवं JSLPS)

कार्यक्रम सं.	12
बैठक की तिथि	11.05.16
बैठक सं	55

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पर चर्चा ...

**अगली SLBC बैठक की तिथि :
10 अगस्त , 2016**